प्रभारी सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में Executive MBA Course हेतु विभिन्न अभियंत्रण विभागों के साथ बैठक दिनांक 18.01.2018 का कार्यवृत्त

प्रभारी सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में part time executive MBA course कर चुके अभियन्ताओं तथा सम्बन्धित विभागों का feedback प्राप्त करने हेतु आयोजित बैठक में लघु सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, ग्रामीण अभियंत्रण, यू0पी0सी0एल0, यू0जे0वी0एन0एल0 एवं उरेडा के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उपस्थितिः–

1. डा0 ए0सी0 जोशी, निदेशक (एच0आर0), यू0जे0वी0एन0एल0।
2. श्री आर0सी0 पुरोहित, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग।
3. श्री के0बी0 चौबे, जी0एम0 (एच0आर0), यू0पी0सी0एल0।
4. श्री ए0के0 त्यागी, सी0पी0ओ0, उरेडा।
5. श्री राजेन्द्र सिंह, डी0जी0एम0, यू0जे0वी0एन0एल0।
6. श्री जे0पी0 भाष्कर, स्टाफ ऑफिसर, लघु सिंचाई।
7. श्री सुभाष चन्द्र, एस0एस0ओ0(बजट), सिंचाई।
8. श्री एस0सी0 पन्त, एस0ई0, पेयजल निगम।
9. श्री आर0के0 रोहिला, सचिव प्रशासन, जल संस्थान।
10. श्री जितेन्द्र सिंह, एस0पी0ओ0, यू0पी0सी0एल0।
11. श्री आशुतोष कौशिक, एस0ई0(एम0) आर0डब्ल्यू0डी0।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि UPES द्वारा वर्तमान में संचालित Executive MBA Course लाभप्रद है, परन्तु इसका प्रत्यक्ष लाभ शायद विभागों को प्राप्त न हो लेकिन बड़े प्रोजेक्ट की planning, timely completion, inventory management आदि में इसका अप्रत्यक्ष लाभ हुआ है। यह भी अवगत कराया गया कि इस पाठ्यक्रम से चारधाम व्यवस्था, आपदा प्रबन्धन आदि में भी लाभ हुआ है। उक्त के दृष्टिगत सारे विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा इस पाठ्यक्रम को भविष्य में भी संचालित कराये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये, जो निम्नानुसार हैः–

- विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि MBA Course प्राप्त कर चुके अधिकारियों के फीडबैक के अनुसार कोर्स के निर्धारित अवधि में अध्यापन दिवसों को बढ़ाये जाने से लाभ होगा।

- एम0बी0ए0 कोर्स का पाठ्यक्रम सिविल इंजीनिरिंग सम्बन्धित अधिकारियों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। civil engineering के लिए ना ही in-house faculty अच्छी है और ना ही बाहर से अच्छी faculty बुलायी जाती है तथा practical/site visit का प्राविधान पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। पाठ्यक्रम में नयी तकनीक तथा नवीनतम आकड़ों एवं विषयों का समावेश किया जाना बेहतर होगा।
- एम0बी0ए0 कोर्स के पाठ्यक्रम में केवल theoretical study रखी गयी है। अर्न्तराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर, जो infrastructure development हुये है, उनका exposure visit कराने का प्राविधान पाठ्यक्रम में कराया जा सकता है तथा पाठयक्रम के अन्त में प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसी विषय पर submit किया जाना अधिक उपयोगी व लाभप्रद होगा।
- MBA Course को लाभप्रद बनाये जाने के लिए, UPES को विभागों के साथ विचार–विमर्श कर need assessment किये जाने के उपरान्त पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना उपयुक्त होगा।
- वर्तमान MBA course में अधिकांश Case Studies अमेरिका से लिए गये है। अतः कोर्स को अधिक लाभप्रद बनाने हेतु case studies अन्य देशों तथा राष्ट्रीय व अन्य प्रदेशों से भी लिए जाय।
- तकनीकी विभागों के साथ–साथ सचिवालय, विभागों तथा जनपद स्तर के प्रशासकीय अधिकारियों को भी part time MBA कराया जाना भी राज्य हित में उचित होगा।
- MBA Course के पश्चात प्रशिक्षित अधिकारियों को विभाग में, नई व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने में कठिनाई होती है, इसके लिए विभागीय कार्य प्रणाली, नयी व्यवस्था की अनुमति नहीं देती है। समय के साथ नये एवं प्रभावी दृष्टिकोण अपनाने हेतु विभागीय कार्य प्रणाली में structural change/review की आवश्यकता है।

<u>उक्त के अतिरिक्त विचार–विमर्श में कई महत्वपूर्ण सुझाव निम्नानुसार प्राप्त हुए:–</u>

- उपस्थित विभागीय प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श में अवगत कराया गया कि राज्य के लगभग सभी विभागों में "Planning & Statistical" प्रकोष्ठ है परन्तु उनका न तो आपस में, न ही नियोजन विभाग के साथ अपेक्षित समन्वय है। अतः विभागों के मध्य, बेहतर समन्वय, सूचनाओं के आदान–प्रदान तथा sharing of knowledge/best practices/innovation हेतु नियोजन विभाग के तत्वाधान में सभी विभागों के "Planning & Statistical" प्रकोष्ठ के साथ "Planning & Statistical Circle" बनाया जाय। प्रकोष्ठ की बैठक 15 दिन या आवश्यकतानुसार की जाय ताकि विभागों के "Planning & Statistical" से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार–विमर्श किया जा सके।

- विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राज्य के अभियांत्रिकी विभागों द्वारा कई अच्छे कार्य किये गये है परन्तु उनका अभिलेखीयकरण न होने के कारण अन्य जगहों पर replication नहीं हो पा रहा है। विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा नियोजन विभाग से अभियांत्रिक विभागों के good practices & innovation के अभिलेखीकरण तथा उसे साझा करने हेतु workshop/seminar आयोजित करने की अपेक्षा की गयी।
- MBA Course के अलावा सचिवालय, विभागों तथा जिलों में कार्यरत अधिकारियों को प्रबन्धन एवं क्षमता विकास के "अल्प अवधि कोर्स" कराये जा सकते है, जिसमें case studies तथा innovative practices को साझा किया जा सकता है।
- सचिवालय तथा विभागों को paper less करने तथा कार्यों को त्वरित गति से सम्पन्न किये जाने हेतु record keeping तथा Enterprise Resource Planning (ERP) को लागू करते हुए पारदर्शी प्रशासन की ओर बढ़ा जा सकता है। यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा कुछ कार्य कराये गये है, जिससे कार्यालय प्रबन्धन सुविधाजनक हो गया है।

अन्त में उपरोक्त बिन्दुओं का उच्च स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के आश्वासन के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
प्रभारी सचिव।

पत्रांक संख्या : 137/67/रा0यो0आ0/2017 दिनांक 29 जनवरी, 2018

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. विभागाध्यक्ष, सिंचाई/पेयजल निगम/लघु सिंचाई/जल संस्थान/लोक निर्माण विभाग/आवास/नगर विकास/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/यू0पी0सी0एल0/पिटकुल एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0/उरेडा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
प्रभारी सचिव।